

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
71वीं बैठक दिनांक 29 नवम्बर, 2019
कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 71वीं बैठक दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को श्री उत्पल कुमार, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में श्री अमित नेगी, सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन, श्री सुनील चावला, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, श्री विजय रंजन, मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, श्री बरकत अली, महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, उप महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक एंव शासकीय विभागों के उच्च अधिकारी, समस्त बैंकों के नियंत्रक उपस्थित थे।

बैठक में एजेण्डेवार विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रगति की समीक्षा एंव महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गयी :

प्राकृतिक आपदा – राहत उपाय (बाढ़ग्रस्त क्षेत्र) :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 2/6/2011-एफ.आई.(सी.-47940) दिनांक 14 अगस्त, 2019 जो गुजरात एवं उत्तराखण्ड राज्यों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय करने से संबंधित है, के संदर्भ में आपदा ग्रस्त क्षेत्र घोषित किये जाने के संबन्ध में सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा प्रेषित पत्र के अनुक्रम में जिलाधिकारियों के स्तर से किसी विशेष बड़ी हानि की सूचना नहीं दी गयी है। यद्यपि इस विषयक एक पत्र पुनः जिलाधिकारियों को प्रेषित किया गया है, जिसके अनुक्रम में यदि कोई क्षेत्र विशेष के बारे में सूचना उपलब्ध होने पर इस सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही कर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को सूचित कर दिया जायेगा।

अल्पावधि एवं दीर्घावधि फसल ऋण (Short and Long Term Crops) :

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रेषित अल्पावधि एवं दीर्घावधि फसल की समय सारणी (Cropping Season), जो कि सदन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी थी, को सदन द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, जिसकी सूचना सभी बैंकों को प्रेषित की जा रही है। अतः सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या DBR.No.BC.2/21.04.048/2015-16 दिनांक 01.07.2015 के अनुरूप कृषि फसलों से सम्बन्धित ऋणों में गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) का निर्धारण अल्पावधि एवं दीर्घावधि फसलों के आधार पर करें।

Constitution of a Sub-Committee on Deepening of Digital Transaction :

सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि है कि इस विषयक नयी कमेटी के गठन हेतु शासनादेश प्रक्रियाधीन है।

Digital District Programme – 100% Digitization :

सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि है कि इस विषयक विस्तृत विवरण एवं कार्ययोजना के लिये भारतीय रिजर्व बैंक व राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को निर्देशित किया गया है, जो कि अभी प्रक्रियाधीन है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि स्कूल, कालेज, मण्डी समिति तथा राज्य में स्थित सरकारी विभागों द्वारा डिजीटल लेनदेन हेतु पी.ओ.एस. मशीन, रूपये डेबिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड आदि का उपयोग किए जाने हेतु कार्ययोजना बनायी जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक राज्य स्तरीय समीक्षा कमेटी मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो अभी प्रक्रियाधीन है।

Online Portal – Government Sponsored Schemes :

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि पोर्टल में दिनांक 05 नवम्बर, 2019 के बाद के डाटा प्रदर्शित हो रहे हैं। सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन द्वारा संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया विभाग एन.आर.एल.एम. पोर्टल संचालन हेतु आई.डी. एवं पासवर्ड सभी बैंक नियंत्रकों, अग्रणी जिला प्रबन्धकों एंव राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को उनकी अग्रिम कार्यवाही हेतु शीघ्र उपलब्ध करायें। प्रबन्धकों एंव राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को उनकी अग्रिम कार्यवाही हेतु शीघ्र उपलब्ध करायें। विभाग द्वारा पोर्टल के परिचालन / हैण्डहोल्डिंग हेतु प्रशिक्षण सभी बैंकों को दिया गया है। इसी अनुक्रम में विभाग द्वारा पोर्टल के परिचालन / हैण्डहोल्डिंग हेतु प्रशिक्षण सभी बैंकों को दिया गया है। इसी अनुक्रम में दिनांक 18 नवम्बर, 2019 को आयोजित ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदया द्वारा विभाग को निर्देशित किया गया था कि वे एक बार पुनः बैंकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड एवं बैंक नियंत्रकों को योजनांतर्गत प्रगति की निगरानी / अनुश्रवण हेतु आई.डी. तथा पासवर्ड उपलब्ध कराएं।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग का पोर्टल तैयार हो गया है जिसका यू.आर.एल. www.nulm.gov.in है, जिसमें उत्तराखण्ड में स्थित बैंकों के डाटा प्रदर्शित हो रहे हैं तथा पोर्टल में कार्य प्रक्रियाधीन है। उक्त पोर्टल में आई.डी. एवं पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है तथा पोर्टल में सूचना के अतिरिक्त Input के right बैंक नियंत्रकों, अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराएं।

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान – पोर्टल बनाये जाने के संबंध में विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वे दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 तक पोर्टल तैयार कर लेंगे। सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन द्वारा संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है कि विभाग शीघ्र पोर्टल बनायें तथा पोर्टल संचालन हेतु आई.डी. एवं पासवर्ड सभी बैंक नियंत्रकों, अग्रणी जिला प्रबन्धकों एंव राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को शीघ्र उपलब्ध करायें।

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना :

विभाग द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एंव दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना के पोर्टल पर कार्य प्रक्रियाधीन है तथा शीघ्र ही पोर्टल तैयार करने का आश्वासन दिया गया है।

Revamp of Lead Bank Scheme – SLBC Data Flow and its management :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा इस विषय में सदन को पूर्ण जानकारी देते हुये अवगत कराया गया है कि इस विषयक चार बैठक आयोजित की जा चुकी है तथा सम्बन्धित विषय के लिए 15 बैंकों को सम्मिलित करते हुए क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है, जो इस सम्बन्ध में अपने सुझाव विस्तृत रूप से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही इस विषय में एक आंतरिक समिति भी गठित की गयी है, जो इस कार्य में पहले से कार्यरत वैन्डर द्वारा पूर्व में दी जा रही सेवाओं/लागत के अन्तर को आंकलन करते हुये अपनी संस्तुती नये साप्टवेयर एंव वैन्डर को hire करने हेतु देगी, जिसके आधार पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा इस विषय पर सक्षम स्तर से निर्णय लिया जायेगा।

इस विषयक एक बैठक दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को आहूत की गयी थी, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली कंपनी (M/s Softrack InfoSolutions Pvt. Ltd.) को सॉफ्टवेयर परिचालन / हैण्डहोल्डिंग पर प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया गया था, जिसमें सभी बैंकों के प्रतिनिधियों, भारतीय रिजर्व बैंक, अग्रणी जिला प्रबन्धकों एंव आंतरिक कमेटी के सदस्य उपस्थित थे।

वित्तीय समावेशन – बैंकिंग नेटवर्क एवं वित्तीय साक्षरता :

Villages inadequately covered or uncovered by Financial Infrastructure on Jan Dhan

Darshak GIS App/ Business Correspondent :

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य में बैंकिंग हेतु आधारभूत सुविधाओं से आनाच्छादित गांव, जिन्हे बैंकिंग आधारभूत सुविधाओं से बैंकों/बी.सी./इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंकों से आच्छादित किया गया है, का जमीनी स्तर पर भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए कि कोई गांव बैंकिंग सुविधाओं से वंचित न रह जाय और यदि वंचित रह जाता है तो वहां पर बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध करायी जानी चाहिये।

महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी अग्रणी जिला प्रबन्धक उनके जिले से संबंधित सभी गांव का जन-धन दर्शक ऐप/भौतिक सत्यापन के माध्यम से किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित गांव के विषय में स्थानीय स्तर से जानकारी प्राप्त कर इसकी पुष्टि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को 15 दिसम्बर, 2019 तक प्रेषित करें कि उनके जिले में स्थित सभी गांव इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक को आवंटित कर विषय को डी.एल.आर.सी. की बैठक में अनुमोदित कर सम्बन्धित बैंक नियंत्रक व राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को भी प्रेषित करें तथा सम्बन्धित बैंक शाखाओं/बैंक नियंत्रकों/इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक से इसका follow up करते हुये उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कुट्टी गांव : मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा कुट्टी गाँव में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होने के विषय में पूछे जाने पर अग्रणी जिला प्रबन्धक, पिथौरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि कुट्टी गाँव में बी.सी. नियुक्त है, लेकिन वहाँ पर कनेक्टिविटी की समस्या है। इस पर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अग्रणी जिला प्रबन्धक, पिथौरागढ़ को निर्देशित किया गया कि वे इस कार्य हेतु प्राथमिकता के तौर पर विस्तृत रिपोर्ट राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराएं कि क्या संबंधित बी.सी. द्वारा किए गए लेन-देन निरंक हैं अथवा वहाँ पर किस प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं तथा गाँव की आबादी कितनी है।

वी.सैट की स्थापना

महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संबंधित बैंकों को निर्देशित किया गया कि जहाँ वी.-सैट स्थापित किए जा चुके हैं अथवा शाखाएं वी.-सैट पर हैं, ऐसे स्थानों पर वैकल्पिक कनेक्टिविटी को भी चेक कराएं, जिससे कि तदानुसार वैकल्पिक कनेक्टिविटी मोड में शिफ्ट करते हुए बैंकिंग सेवाओं में सुधार किया जा सके।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबाड़ द्वारा अवगत कराया गया कि मोबाइल बैन, पी.ओ.एस. मशीन, वी.-सैट, बी.सी. सर्किफिकेशन कोर्स आदि पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है। अतः इस विषय में नाबाड़ के स्तर से पूर्ण सहयोग किया जाएगा। इसी विषय में दिनांक 13 नवम्बर, 2019 को बैंकरहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक में सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा संबंधित बैंक को निर्देशित किया गया कि उन्हें आवंटित गाँव में स्थापित वी.-सैट समिति, उत्तराखण्ड द्वारा बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे। की कनेक्टिविटी एवं बाधित कनेक्टिविटी की रिपोर्ट राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे।

Business Correspondent Certification – Graded Certification Process :

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को विस्तार से अवगत कराया गया कि सभी बैंक उनके द्वारा नियुक्त किए गए पुराने बी.सी. को अधिकतम मार्च, 2022 तक तथा नए बी.सी. को 09 माह के अंदर बी.सी. सर्टिफिकेशन कोर्स अवश्य कराया जाना है तथा कोर्स में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति नाबाड़ द्वारा किए जाने का प्रावधान है।

वार्षिक ऋण योजना एवं प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण उपलब्धि :

वार्षिक ऋण योजना इप्रतिशतकरा दरमें :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के विषय में सदन को अवगत कराया गया कि वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा द्वितीय त्रैमास हेतु निर्धारित मानक **40** प्रतिशत के सापेक्ष **47** प्रतिशत की प्रगति दर्ज की गयी है, जो कि गत वर्ष सितम्बर, 2018 के सापेक्ष 7 प्रतिशत अधिक है। सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन द्वारा फसली ऋण में और अधिक प्रगति दर्ज किए जाने की अपेक्षा की गयी है।

सहम, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME) :

निदेशक, उद्योग द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 02 दिसम्बर, 2019 को उद्योग संवर्धन हेतु सिडबी द्वारा अपराह्न 03:00 बजे से 06:00 बजे तक स्टेट आउटरीच प्रोग्राम (ज्ञान प्रसार और अपेक्षा को सूचीबद्ध करने हेतु) आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार के अधिकारियों, एम.एस.एम.ई.-डी.आई., जिला उद्योग केंद्र, अग्रणी जिला प्रबंधक, उद्योग संघों एवं एम.एस.एम.ई. आदि विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा।

हुए प्राप्त करने वाले हैं। उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से उद्योग विभाग से नए विकसित किए जाने वाले एम.एस.एम.ई. कलस्टर की सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा गया, जिस पर निदेशक, उद्योग द्वारा बताया गया कि अभी इस विषय पर वांछित निर्णय प्रक्रियाधीन है।

द्वारा बाधा देया जा सकता है। इसी कारण से उपलब्ध कराएं, जिससे कि सभी बैंकों को तदानुसार सूचित किया जा सके।

किसान क्रेडिट कार्ड संतप्त (KCC saturation) अभियान :

के राज्य अन्य जिला न गा परता है। इसके अलावा यह एक अन्य बड़ी विषय है कि सभी बैंक अग्रणी जिला प्रबंधकों के नेतृत्व मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी बैंक अग्रणी जिला प्रबंधकों के नेतृत्व में योग्य किसानों को के सी.सी. का लाभ पहुँचाने हेतु कैम्प लगाकर उन्हें कवर करें। इस विषय पर

सहायक निदेशक, कृषि निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में 8.81 लाख सक्रिय किसान हैं, जिसमें से वर्तमान में लगभग 6 लाख किसानों को के.सी.सी. जारी कर लाभान्वित किया जा चुका है तथा शेष 2.81 लाख सक्रिय किसानों को के.सी.सी. जारी किए जाने की संभावना है। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा कृषि विभाग से सदन के माध्यम से अपेक्षा की गयी वे राज्य में कार्यरत सक्रिय किसानों की गाँव-वार एवं जिलेवार सूचना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि उपलब्ध डाटा के आधार पर बैंक राज्य में ऋणी एवं गैर-ऋणी किसानों को के.सी.सी. वितरित कर सकें। इस पर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा कृषि विभाग को निर्देशित किया गया कि वे गाँव-वार, जिले-वार सक्रिय किसानों की सूची सॉफ्ट कॉपी में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराएं तथा जिले के मुख्य कृषि अधिकारी को निर्देशित करें कि वे बैंकों द्वारा के.सी.सी. जारी करने हेतु विशेष अभियान में अपने विभाग का शत प्रतिशत योगदान दें।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :

मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्वर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लि. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2019 के अंतर्गत संसूचित फसल गेंहू एवं मसूर के लिए बीमा प्रीमियम 15 दिसम्बर, 2019 तक संबंधित ऋण खाते से नामे करें तथा संबंधित डाटा पोर्टल पर 31 दिसम्बर, 2019 तक अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करें। मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी 2019-20 के अंतर्गत संसूचित फसल सेब, आदू, माल्टा, संतरा, मौसमी, आम, लीची, आलू, टमाटर एवं मटर के लिए बीमा प्रीमियम 31 दिसम्बर, 2019 तक संबंधित ऋण खाते से नामे करें तथा संबंधित डाटा पोर्टल पर 15 जनवरी, 2020 तक अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करें।

ऋण-जमा अनुपात :

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे उनकी बैंक शाखाओं में विभिन्न योजनांतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण में तीव्रता लाएं, जिससे कि बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि दर्ज हो सके।

सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनांतर्गत गैर-निष्पादित आस्तियाँ :

सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनांतर्गत बढ़े हुए एन.पी.ए. प्रतिशत के विषय में सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड द्वारा VCSGSY, SJSRY, SGSY & DEDS के विषय में अपेक्षा की गयी है कि इन योजनाओं में बढ़ते एन.पी.ए. के कारणों को जानना आवश्यक है, जिससे कि एन.पी.ए. को कम करने हेतु उचित उपाय किए जा सकें। साथ ही योजना में किसी कमी के कारण या लाभार्थी चयन में त्रुटि के कारण एन.पी.ए. बढ़ रहे हैं, तो उसका निराकरण संबंधित विभाग द्वारा किया जाना चाहिए।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा DEDS के बारे में सदन को अवगत कराया गया कि उक्त योजना में अनुदान राशि उपलब्ध है। अतः इस योजनांतर्गत एन.पी.ए. का प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए, जिस पर बैंकों द्वारा कहा गया कि पोर्टल से अनुदान राशि अवमुक्त न होने के कारण एवं पोर्टल की गति धीमी होने के कारण अनुदान राशि अवमुक्त नहीं हो पाती है, जिससे खाते एन.पी.ए. श्रेणी में आ जाते हैं। इस पर नाबार्ड द्वारा अवगत कराया गया कि बैंक DEDS योजना के अंतर्गत ऋण राशि स्वीकृत करने के बाद ऋण वितरण के पूर्व सब्सिडी को पोर्टल पर ब्लॉक करने की कार्यवाही करें, जिससे कि ऋण वितरण के बाद अनुदान राशि समाप्त होने की समस्या न आए। सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी बैंक योजनांतर्गत, जहाँ एन.पी.ए. का प्रतिशत अधिक है की सूची विस्तृत विवरण के साथ संबंधित विभाग के साथ साझा करें तथा उसकी एक सूची राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को भी उपलब्ध कराएं।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सुझाव दिया गया कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एवं दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास योजना के अंतर्गत निर्मित होटल, मोटल को OYO के साथ

Tie-Up करने की कार्यवाही विभाग स्तर से की जाए, जिससे Occupancy की उपलब्धता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि सभी बैंक एन.पी.ए. धनराशि की सूचना देते समय write off किए गए एन.पी.ए. खातों का विवरण भी योजनांतर्गत एन.पी.ए. में शामिल करें। साथ ही Special mentioned Accounts / Stressed Accounts (SMA – 0 to SMA – 2) की सूचना एन.पी.ए. खातों के संबंध में पृथक रूप से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराएं।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि बैंकों द्वारा जारी किए गए वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष वसूली में संबंधित विभागों का सहयोग अपेक्षित है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) की गतिविधियों की समीक्षा :

सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन द्वारा आरसेटी संस्थानों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राप्त रोजगार का प्रतिशत जो कि 60 प्रतिशत से कम (56 प्रतिशत) है, का कारण जानना चाहा, जिस पर राज्य निदेशक, आरसेटी संस्थान उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि आरसेटी संस्थान से प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों के ऋण आवेदन पत्रों को बैंकों द्वारा निरस्त अथवा प्रशिक्षणार्थियों द्वारा ऋण हेतु आवेदन न किया जाना है। इसी अनुक्रम में महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बताया गया कि बैंकों के Credit off take छूँकि कम चल रहा है, जिसको बढ़ाने हेतु बैंक प्रयासशील हैं। अतः ऐसे 10 ऋण प्रस्ताव जो गैर-तकनीकी एवं गलत कारणों से निरस्त / वापस किए गए हैं, का विवरण राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराएं।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व्यक्तिगत (NULM Individual) :

सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड द्वारा योजनांतर्गत हुई कम प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा विभाग को निर्देशित किया गया कि वे लक्ष्य के सापेक्ष 50–60 प्रतिशत अधिक ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि एन.यू.एल.एम. पोर्टल में बैंकों को केवल View Right दिए गए हैं, अतः सभी बैंक उनके द्वारा निस्तारित किए गए ऋण आवेदन पत्रों का विवरण संबंधित विभाग को पोर्टल में अपलोड करने हेतु प्रेषित करें।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि बैंक शाखाओं को विभाग से प्राप्त ऋण आवेदन पत्र 6899 के सापेक्ष 3591 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 07 अक्टूबर, 2019 तथा 14 नवम्बर, 2019 को शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों के संबंध में हूई बैठक में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के फलस्वरूप बैंकों द्वारा अपेक्षित प्रगति दर्ज की गयी है। यह भी अवगत कराया गया कि सितम्बर, 2019 तक के ऋण आवेदन पत्रों का manually निस्तारण कर दिया जाए, अक्टूबर, 2019 से ऋण आवेदन पत्र पोर्टल पर अपलोड किए जाएं तथा पोर्टल क्रियान्वित होने की तिथि 01 अक्टूबर, 2019 से प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों का पूर्ण विवरण राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि प्रगति की मॉनिटरिंग कर संबंधित बैंकों से ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करवाने हेतु अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके।

प्रधानमंत्री रोजगार सूजन प्रोग्राम :

सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि आपकी अध्यक्षता में मासिक अंतराल पर आयोजित समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों / सुझावों के सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं। इसी अनुक्रम में उन्होंने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि वे मासिक अंतराल पर आहूत होने वाली आगामी बैठक से पूर्व योजनांतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण कर, प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निदेशक, उद्योग द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम के अंतर्गत पोर्टल के माध्यम से आवेदित ऋण आवेदन पत्रों की जाँच का प्रावधान है, फिर भी अधिक संख्या में ऋण आवेदन पत्र निरस्त हो रहे हैं, जिनके वास्तविक कारणों को जानना आवश्यक है। इस पर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे उचित कारणों को अंकित करते हुए ऋण आवेदन पत्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में विभाग ऋण आवेदन पत्रों का चयन करते समय उन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए। साथ ही संबंधित आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के निरस्त होने के कारणों से अवगत कराएं तथा तदानुसार वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करवाकर, आवेदन पत्र पुनः बैंक शाखाओं को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करें। इसी अनुक्रम में महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संबंधित विभाग को सुझाव दिया गया कि वे संबंधित ऋण आवेदनकर्ताओं का मार्गदर्शन करें, जिससे कि ऋण आवेदन पत्रों के निरस्तीकरण में कमी संभव हो सके।

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना :

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा योजनांतर्गत प्रगति की समीक्षा करते हुए विभाग से जानना चाहा कि किन-किन बैंकों में अधिक संख्या में ऋण आवेदन पत्र लम्बित हैं। इस पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, यूनियन बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं में ऋण आवेदन पत्र लम्बित हैं। इसी अनुक्रम सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि मासिक अंतराल पर आहूत होने वाली आगामी बैठक में लम्बित आवेदन पत्र के संबंध में समीक्षा की जाएगी।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे लम्बित आवेदन पत्रों के कारणों से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को अवगत कराएं।

प्रधानमंत्री आवास योजना :

सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन द्वारा योजनांतर्गत प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। साथ ही लोकसंपर्क के माध्यम से निश्चित आय वाले वर्ग यथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पुलिस कर्मी, सैनिक कल्याण बोर्ड, सरकारी विभागों तथा अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों को योजना के प्रति जागरूक करें, जिससे वे योजना से लाभान्वित हो सकें।

उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 391 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऋण वितरित कर लाभान्वित किया गया है।

पिरुल नीति :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को पिरुल नीति के संबंध उरेडा विभाग तथा बैंकों के साथ आयोजित बैठक में वित्तपोषण में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु एक चैक लिस्ट तैयार की गयी है, जिसे सभी बैंकों को उनकी अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा विभाग से आग्रह किया गया कि योजनांतर्गत बैंकों में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का विवरण सॉफ्ट कॉपी में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराएं, जिससे कि लम्बित ऋण आवेदन पत्रों के निरस्तारण हेतु कार्यवाही की जा सके।

Advance against Warehouse Receipts :

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत सब्सिडी प्राप्त करने हेतु इकाई Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसी अनुक्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा योजना को किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में एक अच्छा प्रयास बताते हुए इस योजना हेतु शासन स्तर पर एक बैठक कर समुचित कार्ययोजना / रणनीति तैयार करने की अपेक्षा व्यक्त की गयी।

सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि संज्ञान में आया है कि शुगर मिलों द्वारा भुगतान सीधे बैंकों को किया जाता है, जब कि गन्ने का भुगतान क्रमशः किसानों, गन्ना सोसायटी एवं बैंकों को किया जाना चाहिए। इसी अनुक्रम में सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड द्वारा सलाहकार, वित्त (बैंकिंग) को निर्देशित किया गया कि वे इस विषयक विस्तृत जानकारी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराएं, जिससे तदानुसार कार्यवाही की जा सके।

बैठक के अंत में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड द्वारा विभिन्न योजनांतर्गत हुई प्रगति को संतोषजनक बताते हुए कहा कि पूर्व में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा त्रैमासिक अंतराल पर की जाती रही है, लेकिन अब प्रभावी निगरानी हेतु मासिक अंतराल पर प्रगति की समीक्षा की जा रही है, जिसमें जिला स्तर पर वांछित प्रगति दर्ज करने हेतु वी.सी. के माध्यम से जिलाधिकारियों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण बैठकों में कतिपय बैंकों द्वारा प्रतिभाग न किए जाने को गम्भीरता से लेते हुए निर्देशित किया गया कि सभी संबंधित विभाग एवं बैंक आवश्यक जानकारी / डाटा सहित आगामी बैठकों में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा 100 प्रतिशत जिला डिजीटाइजेशन के अंतर्गत जिला अल्मोड़ा के चयन की चर्चा करते हुए कहा कि यह राज्य का Role Model है, इसमें न केवल बैंकिंग लेन-देन का डिजीटाइजेशन किया जाए बल्कि सरकारी लेन-देन का भी डिजीटाइजेशन किया जाए, जिसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन एवं विभागों को निर्देशित किया कि वे इस कार्य में बैंकों का सहयोग करें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना जो कि राज्य की महत्वकांक्षी योजना है, के अंतर्गत ऋण आवेदन पत्रों हेतु सिंगल वींडो सिस्टम लागू किया जाए, जिसके पश्चात जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन के बाद स्वतः ही भू-उपयोग परिवर्तन माना जाएगा व संबंधित राजस्व विभाग में भू-उपयोग परिवर्तन नोट किया जाएगा। इस प्रक्रिया से समय की बचत होगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया कि मासिक अंतराल पर आयोजित गत समीक्षा बैठक में रेखीय विभागों को निर्देशित किया गया था कि वे बैंक शाखाओं में विभिन्न ऋण योजनांतर्गत लम्बित आवेदन पत्रों का संज्ञान लेते हुए उनका निस्तारण करवाने में बैंकों से संपर्क कर अनुवर्ती कार्यवाही करें, यदि ऋण आवेदन पत्रों में कोई विसंगति पायी जाती है, तो उसके निदान हेतु आवेदनकर्ता से संपर्क करें, जो ऋण प्रवाह को गति प्रदान करने में सहायक होगा साथ ही जिले के ऋण-जमा अनुपात में वांछित प्रगति दर्ज परिलक्षित होगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी प्रतिभागियों को नववर्ष 2020 की शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की गयी कि दिसम्बर, 2019 त्रैमास में सभी बैंकों द्वारा विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत अच्छी प्रगति दर्ज की जाएगी।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक एक मुश्त निपटान योजना (OTS) "ऋण समाधान 2019–20" ₹ 20.00 लाख तक के बकाया ऋणियों हेतु प्रारम्भ की गयी है, जिसका उद्देश्य कृषि, शिक्षा, लघु एवं मध्यम उद्यमों में गैर-निष्पादित आस्तियों के प्रतिशत को कम करना तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में वसूली को प्रोत्साहित करना है।

अंत में महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक को मार्गदर्शन करने हेतु तथा विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं बैंकों को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बैठक की कार्यवाही कवर करने हेतु धन्यवाद दिया गया।

सहायक महाप्रबंधक
(राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड)
